

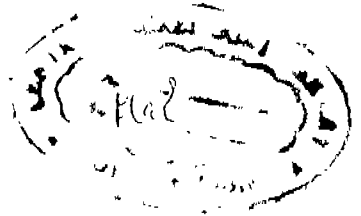


भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 8]
No. 8]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 10, 1997/फाल्गुन 19, 1918
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 10, 1997/PHALGUNA 19, 1918

आन्ध्रा बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

अधिसूचना

हैदराबाद, 16 जनवरी, 1997

अधिसूचना सं. 666/3/ए. 1/1079.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 12 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आन्ध्रा बैंक का निदेशक मण्डल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(1) ये विनियम आन्ध्रा बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1996 कहलाएंगे :

(2) इन विनियमों में अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधितानुसार, ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. आन्ध्रा बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1982 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा जाएगा) में, विनियम 4 के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्—

(ग) मध्य प्रबंधन श्रेणी :

वेतनमान III रु. 8050-230-9200-250-9700

वेतनमान II रु. 6210-230-8740

(घ) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी :

वेतनमान I रु. 4250-230-4940-350-5290-230-8050

4(3) उप विनियम (1) और (2) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि बैंक के लिए हर समय इन सभी श्रेणियों में अधिकारी रखना अपेक्षित है।

3. मूल विनियमों में, विनियम 5 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्

5(1) विनियम 4(2) के उपबंधों के अध्वधीन, दिनांक 01.11.1992 को या उसके बाद से, वेतनवृद्धियां निम्नलिखित उप खण्डों के अध्वधीन दी जाएंगी।

(क) विनियम 4 के उपवर्णित विभिन्न वेतनमानों में विनिर्दिष्ट वेतनवृद्धियां, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अध्वधीन वार्षिक आधार पर प्रोद्भूत होंगी और वे जिस महीने में देय होती हैं उस महीने की पहली तारीख को दी जाएंगी।

(ख) वेतन मान I तथा II के अधिकारियों को, अपने संबंधित वेतनमानों के अधिकतम पर पहुँचने के एक वर्ष के पश्चात्, अगले उच्च वेतनमान में अवरोध वेतनवृद्धि (यों) सहित आगे की वेतनवृद्धियाँ केवल नीचे (ग) में निर्दिष्ट आधार पर सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार दी जाएंगी बशर्ते कि वे दक्षतारोध को पार कर लें।

4(1) 01.11.1987 को तथा उसके बाद, प्रत्येक श्रेणी के सामने विनिर्दिष्ट वेतनमान लागू होंगे :

(क) शीर्ष कार्यपालक श्रेणी :

वेतनमान VII रु. 6400-150-7000

वेतनमान VI रु. 5950-150-6550

(ख) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी :

वेतनमान V रु. 5350-150-5950

वेतनमान VI रु. 4520-130-4910-140-5050-150-5350

(ग) मध्य प्रबंधन श्रेणी :

वेतनमान III रु. 4020-120-4260-130-4910

वेतनमान II रु. 3060-120-4260-130-4390

(घ) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी :

वेतनमान I रु. 2100-120-4020

4(2) 01.07.1993 को तथा उसके बाद, प्रत्येक श्रेणी के सामने विनिर्दिष्ट वेतनमान लागू होंगे :

(क) शीर्ष प्रबंधन श्रेणी :

वेतनमान VII रु. 12650-300-13250-350-13600-400-14000

वेतनमान VI रु. 11450-300-12650

(ख) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी :

वेतनमान V रु. 10450-250-11450

वेतनमान IV रु. 8970-230-9200-250-10450

(ग) ऊपर (ख) में उल्लिखित अधिकारियों सहित, मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II तथा III के अधिकतम पर पहुँचने वाले अधिकारियों को, यथास्थिति, वेतनमान II तथा III के अंतिम प्रक्रम पर पहुँचने के पश्चात् प्रत्येक 3 वर्षों की सेवा पूरी होने पर अवरोध वेतनवृद्धि (यां) दी जाएगी/जाएंगी। वेतनमान II के अंतिम प्रक्रम पर पहुँच चुके अधिकारियों के मामले में रु. 230/- की अधिक से अधिक दो वेतनवृद्धियाँ दी जाएंगी तथा वेतनमान III के अंतिम प्रक्रम के अधिकारियों के मामले में रु. 250/- की एक वेतनवृद्धि दी जाएगी।

परंतु 1.11.1994 को और उसके बाद से, मूल वेतनमान III के अधिकारियों को अर्थात् जो वेतनमान III में भर्ती या पदोन्नत हुए हैं, दूसरी अवरोध वेतनवृद्धि पहली अवरोध वेतनवृद्धि पाने के तीन वर्ष पश्चात् प्रदान की जाएगी।

टिप्पणी :

अगले उच्चतर वेतनमान में की गई ऐसी वेतनवृद्धियों को पदोन्नति नहीं माना जाएगा। ऐसी वेतनवृद्धियाँ पाने के पश्चात् भी अधिकारी को, यथास्थिति, उसके अपने मूल पद के वेतनमान II तथा III के ही विशेषाधिकार, परिलब्धियाँ, इयूटी, उत्तरदायित्व अथवा पद मिलेंगे।

(2) नियत तारीख को या उसके पश्चात् भारतीय बैंकर संस्थान की प्रमाणपत्रित एसोसिएट (सी ए आइ आइ बी) परीक्षा का प्रत्येक भाग उत्तीर्ण करने पर वेतनमान में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि प्रदान की जाएगी।

स्पष्टीकरण I

जिस अधिकारी ने नियत तारीख से पहले अधिकारी के रूप में भारतीय बैंकर संस्थान की प्रमाणपत्रित एसोसिएट (सी ए आइ आइ बी) परीक्षा का भाग I या भाग II उत्तीर्ण कर लिया हो, उसे नियत तारीख से, यथास्थिति, अतिरिक्त वेतनवृद्धि अथवा वेतनवृद्धियाँ दी जाएंगी बशर्ते कि उसने उक्त परीक्षा के दोनों भाग उत्तीर्ण करने पर कोई वेतनवृद्धि न ली हो अथवा केवल एक वेतनवृद्धि ली हो।

स्पष्टीकरण II

- (क) 01.11.1987 को तथा उसके बाद से वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने वाले अथवा पहुँच चुके ऐसे अधिकारियों को जो पदोन्नति पाए बिना और आगे नहीं जा सकते, सरकारी मार्गनिर्देशों के अधीन, यदि कोई हों, सी ए आइ आइ बी परीक्षा उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप अतिरिक्त वेतनवृद्धियों के स्थान पर निम्नानुसार व्यावसायिक अर्हता भत्ता दिया जाएगा।

जिन्होंने सी ए आइ आइ बी का केवल भाग I उत्तीर्ण किया है (i) एक वर्ष पश्चात् रु. 100/- प्रति माह जिसमें से रु. 75/- अधिवर्षिता लाभ के लिए गिने जाएंगे।

जिन्होंने सी ए आइ आइ बी के दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिए हैं (i) एक वर्ष पश्चात् रु. 100/- प्रति माह जिसमें से रु. 75/- अधिवर्षिता लाभ के लिए गिने जाएंगे।

(ii) दो वर्ष पश्चात् रु. 250/- प्रति माह जिसमें से रु. 200/- अधिवर्षिता लाभ के लिए गिने जाएंगे।

- (ख) 01-11-1994 को तथा उसके बाद से, अन्य बातें समान होने पर, व्यावसायिक अर्हता भत्ते की मात्रा निम्नानुसार पुनरीक्षित रहेंगी :

जिन्होंने सी ए आइ आइ बी का केवल भाग I उत्तीर्ण किया है (i) वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने पर एक वर्ष पश्चात् रु. 120/- प्रति माह।

जिन्होंने सी ए आइ आइ बी के दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिए हैं (i) वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने पर एक वर्ष पश्चात् रु. 120/- प्रति माह।

(ii) वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने पर दो वर्ष पश्चात् रु. 300/- प्रति माह।

परन्तु विनियम 5(3) के अनुसार नियत वैयक्तिक भत्ता प्राप्त करने के पात्र अधिकारी, यथास्थिति, क्रमशः भाग I या II के लिए व्यावसायिक अर्हता भत्ता पाने के एक/दो वर्ष पश्चात् प्राप्त कर सकेंगे।

टिप्पणी:—

- (i) यदि किसी ऐसे अधिकारी को जिसे व्यावसायिक अर्हता भत्ता मिल रहा है, अगले उच्चतर वेतनमान में पदोन्नत किया जाता है तो ऐसे उच्चतर वेतनमान में उसका वेतन निर्धारित करते समय उसे वेतनमान में उपलब्ध वेतनवृद्धियों की सीमा तक, सी ए आइ आइ बी की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अतिरिक्त वेतनवृद्धियाँ दी जाएंगी और यदि वेतनमान में कोई वेतनवृद्धियाँ उपलब्ध नहीं हैं अथवा केवल एक वेतनवृद्धि उपलब्ध है तो अधिकारी वेतनवृद्धि(यों) के एवज में व्यावसायिक अर्हता भत्ता पाने का पात्र होगा।
- (ii) 01-11-1994 को तथा उसे बाद से परिशोधित व्यावसायिक अर्हता भत्ते को महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता तथा अधिवर्षिता लाभों के लिए गिना जाएगा।

- 3(क) जो अधिकारी 01-11-1993 को बैंक की स्थायी सेवा में हैं उन्हें वेतनमान में एक अग्रिम वेतनवृद्धि दी जाएगी। जो अधिकारी 01-11-1993 को परीक्षा पर हैं उन्हें एक अग्रिम वेतनवृद्धि स्थायीकरण के एक वर्ष पश्चात् दी जाएगी।

टिप्पणी :

अग्रिम वेतनवृद्धि के कारण वार्षिक वेतनवृद्धि की तारीख में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

- (ख) जो अधिकारी वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच चुका है या जो 01-11-1993 को अवरोध वेतनवृद्धि(यां) प्राप्त कर चुका है वह 01-11-1993 से नियत वैयक्तिक भत्ता प्राप्त कर सकेगा जो अंतिम आहरित वेतनवृद्धि और उस पर 01-11-1993 को देय महंगाई भत्ता, तथा विनियम 22 के अनुसार लागू दरों पर मकान किराया भत्ते की मात्रा के बराबर होगा । यहां नीचे दिया गया नियत वैयक्तिक भत्ता तथा साथ ही साथ महंगाई भत्ता, यदि कोई हो, संपूर्ण सेवा अवधि के लिए अवरुद्ध कर दिया जाएगा ।

वेतनवृद्धि घटक	01-11-1993 को महंगाई भत्ता	जहां बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है वहां देय कुल नियत वैयक्तिक भत्ता
(क)	(ख)	(ग)
230	5.79	236
250	6.30	257
300	7.56	308
400	10.08	411

टिप्पणी :

- (i) ऊपर (सी) में निर्दिष्ट नियत वैयक्तिक भत्ता उन अधिकारी कर्मचारियों को देय होगा जिन्हें बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है ।
- (ii) मकान किराया भत्ते के लिए पात्र अधिकारियों को नियत वैयक्तिक भत्ता, विनियम 4 के उप विनियम (2) में निर्दिष्टानुसार संबंधित वेतनमान की अंतिम वेतनवृद्धि प्राप्त कर लेने पर, (क) + (ख) + संबद्ध अधिकारी कर्मचारियों द्वारा आहरित मकान किराया भत्ता होगा ।
- (iii) नियत वैयक्तिक भत्ता पाने वाले वर्ष में देय व्यावसायिक अर्हता भत्ता, यदि कोई हो, अगले वर्ष दिया जाएगा ।
- (iv) नियत वैयक्तिक भत्ते के वेतनवृद्धि घटक को अधिवर्षिता लाभों के लिए गिना जाएगा ।
- (ग) ~~यदि~~ अधिकारी को यह अग्रिम वेतनवृद्धि मिल चुकी है, उसे ऊपर (ख) में उल्लिखित नियत वैयक्तिक भत्ते की प्रमात्रा, वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात् प्राप्त होगी ।

4. मूल विनियमों में, विनियम 21 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्

21(1) 01.11.1987 को तथा उसके बाद से, महंगाई भत्ता योजना इस प्रकार होगी ।

- (i) महंगाई भत्ता अखिल भारतीय औसत श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सामान्य आधार 1960=100 की तिमाही औसत में 600 अंकों के ऊपर 4 अंकों की प्रत्येक वृद्धि अथवा गिरावट के हिसाब से संदेय होगा ।
- (ii) महंगाई भत्ता निम्नलिखित दरों पर संदेय होगा:
- (i) रु. 2,500/- तक 'वेतन' का 0.67%, धन (+)
- (ii) रु. 2,500/- से ऊपर परंतु रु. 4,000/- तक 'वेतन' का 0.55%, धन (+)
- (iii) रु. 4,000/- से ऊपर परंतु रु. 4,260/- तक 'वेतन' का 0.33%, धन (+)
- (iv) रु. 4,260/- से ऊपर 'वेतन' का 0.17%

21(2) 01.07.1993 को तथा उसके बाद से, महंगाई भत्ता निम्नलिखित दरों पर संदेय होगा—

- (i) महंगाई भत्ता अखिल भारतीय औसत श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सामान्य आधार 1960=100 की तिमाही औसत में 1148 अंकों के ऊपर 4 अंकों की प्रत्येक वृद्धि अथवा गिरावट के हिसाब से संदेय होगा ।
- (ii) महंगाई भत्ता निम्नलिखित दरों पर संदेय होगा:
- (क) रु. 4,800/- तक 'वेतन' का 0.35 %, धन (+)
- (ख) रु. 4,800/- से ऊपर रु. परंतु 7,700/- तक 'वेतन' का 0.29 %, धन (+)
- (ग) रु. 7,700/- से ऊपर परंतु रु. 8,200/- तक 'वेतन' का 0.17 %, धन (+)
- (घ) रु. 8,200/- से ऊपर 'वेतन' का 0.09 %

टिप्पणी :

- (i) महंगाई भत्ते के प्रयोजन हेतु 'वेतन' से मूल वेतन तथा अवरोध वेतनवृद्धियां अभिप्रेत हैं ।
 (ii) महंगाई भत्ते के लिए व्यावसायिक अर्हता भत्ते को 01-11-1994 से गिना जाएगा ।

5. मूल विनियमों में, विनियम 22 के उप-विनियम (1) और (2) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :

22. (1) 1-11-1994 को या उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है तो वह जिस वेतनमान में है उसके प्रथम प्रक्रम में मूल वेतन के 4% के बराबर रकम या आवास हेतु मानक किराया, इनमें से जो भी कम हो, वसूल किया जाएगा।
 (2) 1-11-1992 को या उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा मकान नहीं दिया गया है तो वह निम्नलिखित दरों पर मकान किराया भत्ता पाने का पात्र होगा:—

स्तंभ I	स्तंभ II
कार्यस्थल निम्नलिखित स्थानों पर होने पर	देय मकान किराया भत्ता
(i) सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रमुख "ए" वर्ग के नगर तथा समूह "ए" के परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 13% प्रतिमाह
(ii) क्षेत्र I में अन्य स्थान तथा समूह "बी" के परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 12% प्रतिमाह
(iii) क्षेत्र II तथा उपर्युक्त (i) और (ii) के अंतर्गत न आने वाले राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों की राजधानियां	वेतन का 10½% प्रतिमाह
(iv) क्षेत्र III	वेतन का 9½% प्रतिमाह

परंतु यदि कोई अधिकारी किराये की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भत्ता, जिस वेतनमान में वह है उसके प्रथम प्रक्रम के 4% से ऊपर, उसके द्वारा अपने आवास के लिए दिया गया वास्तविक किराया या ऊपर स्तंभ II के अनुसार देय मकान किराया भत्ते का 150%, जो भी कम हो, होगा।

टिप्पणी:

- (i) मकान किराया भत्ते के प्रयोजन हेतु 'वेतन' से मूल वेतन तथा 1-7-1993 को परिशोधित वेतनमान के अनुसार अवरोध वेतनवृद्धियां अभिप्रेत हैं।
 (ii) मकान किराया भत्ते के प्रयोजन हेतु व्यावसायिक अर्हता भत्ते को 1-11-1994 से प्रभावी गिना जाएगा।

6. मूल विनियमों में, विनियम 23 के उप-विनियम (i) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:

- 23.(i) 1-11-1993 को और उसके बाद से, यदि अधिकारी निम्नलिखित सीरणी के स्तंभ I में उल्लिखित किसी स्थान में कार्यरत हो वह उस स्थान के सामने स्तंभ 2 में उल्लिखित दर पर नगर प्रतिकर भत्ता पाने का पात्र होगा।

स्थान	दर
(क) क्षेत्र I के स्थान और गोवा राज्य	मूल वेतन का 4½% अधिकतम रु. 335/- प्रति माह
(ख) 5 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान और राज्यों की राजधानियां तथा चंडीगढ़, पॉण्डिचेरी और पोर्टब्लेयर जो ऊपर (क) में नहीं आते।	मूल वेतन का 3½% अधिकतम रु. 230/- प्रति माह

7. मूल विनियमों में, विनियम 24 के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :

24. (1) अधिकारी अपने परिवार के लिए किए गए वास्तविक चिकित्सा व्यय की निम्नलिखित आधार पर प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा, अर्थात्:—

598-11/97-2

(क) चिकित्सा व्यय

1-11-1994 को और उसके बाद से अधिकारी द्वारा अपने और अपने परिवार के लिए किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति नीचे स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट श्रेणी तथा स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट प्रतिपूर्ति सीमा के अध्वधीन की जाएगी। इसके लिए अधिकारी को अपनी ओर से ही प्रमाण पत्र देना होगा कि उसने यह व्यय किया है और दावा की गई राशि के समर्थन में उसे खर्च का विवरण देना होगा।

सारणी

श्रेणी	वार्षिक
1	2
कनिष्ठ प्रबंधन तथा	रु. 1,500/-
मध्य प्रबंधन श्रेणी	
वरिष्ठ प्रबंधन तथा	रु. 2,000/-
शीर्ष कार्यपालक श्रेणी	

टिप्पणी:

- उपयोग में न आई चिकित्सा सहायता राशि को अधिकारी संचित कर सकता है परंतु संचित राशि किसी भी समय उल्लिखित अधिकतम राशि के तीन गुने से अधिक नहीं होगी।
- चिकित्सा सहायता योजना के अधीन वर्ष 1994 के लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति दो महीने, अर्थात् नवम्बर और दिसम्बर, 1994 के लिए यथानुपात बढ़ाई जाएगी।

स्पष्टीकरण:

इस विनियम के प्रयोजन के लिए अधिकारी के 'परिवार' में उसका पति/पत्नी, पूर्णतः आश्रित संतान और पूर्णतः आश्रित माता-पिता ही शामिल होंगे।

(ख) अस्पताल में भर्ती खर्च :

- 1-11-1994 को और उसके बाद से, अस्पताल में भर्ती होने पर अधिकारी के मामले में 100% और उसके परिवार के सदस्यों के मामले में 75% तक के खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी। सरकार के मार्ग-निर्देशों के अनुसार समय-समय पर निर्धारित उच्चतम सीमा के अध्वधीन बिलों, वाउचरों आदि के आधार पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- अधिकारियों या उनके परिवार के सदस्यों से, यथास्थिति, यह अपेक्षा की जाती है कि वे किसी सरकारी या नगरपालिका अस्पताल में या किसी निजी अस्पताल अर्थात् किसी न्यास, धर्मार्थ संस्थान या धार्मिक मिशन के प्रबंधन के अधीन आने वाले अस्पतालों में भर्ती हों, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में अधिकारीगण या उनके परिवार के सदस्य अथवा दोनों किसी अनुमोदित निजी नर्सिंग होम या बैंक द्वारा अनुमोदित निजी अस्पतालों में भर्ती हो सकते हैं किन्तु ऐसे मामलों में प्रतिपूर्ति ऊपर वर्णित अस्पतालों में भर्ती पर प्रतिपूर्ति योग्य राशि तक सीमित रहेगी।
- 1-1-1994 को या उसके बाद से, मान्यताप्राप्त अस्पताल के प्राधिकारियों और बैंक के चिकित्सा अधिकारी द्वारा घर पर इलाज की आवश्यकता प्रमाणित करने पर निम्नलिखित रोगों के चिकित्सा खर्चों को भी अस्पताल में भर्ती खर्च माना जाएगा और उससे संबंधित चिकित्सा खर्चों की अधिकारी के मामले में 100% तक और उसके परिवार के सदस्यों के मामले में 75% तक प्रतिपूर्ति की जाएगी।
कैंसर, श्वेतारक्तता, थैलसामिया, तपेदिक, पक्षाघात, हृदयरोग, कुष्ठ रोग, गुर्दे की खराबी, मिरगी, पार्किन्सन की बीमारियां, मनोविकार दोष और मधुमेह।

टिप्पणी : (1) घरेलू उपचार के मामले में दवाओं आदि की लागत की प्रतिपूर्ति विशेषज्ञ के नुस्खे में उल्लिखित अवधि के लिए की जाएगी। यदि अवधि का उल्लेख नहीं किया गया है तो प्रतिपूर्ति के प्रयोजन हेतु नुस्खा 90 दिनों तक वैध होगा।

- उक्त उप-विनियम (i) में उल्लिखित चिकित्सा लाभ (जिसमें अस्पताल में भर्ती आदि भी शामिल हैं) के होते हुए भी और उनका पूर्णतया प्रतिस्थापन करते हुए, नियत तारीख को जो चिकित्सा लाभ (जिसमें अस्पताल में भर्ती आदि शामिल हैं) बैंक में उपलब्ध थे, निदेशक-मण्डल उनमें कोई परिवर्तन किए बिना, उन्हें बनाए रखने का विनिश्चय कर सकता है और यदि निदेशक मण्डल ऐसा तय करता है तो सभी अधिकारी चिकित्सा लाभ (जिसमें अस्पताल में भर्ती आदि भी शामिल हैं) के लिए नियत तारीख को बैंक में लागू निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार ही चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे।
- चिकित्सा सहायता और अस्पताल में भर्ती की सुविधाएं निम्नलिखित अधिकारियों को भी दी जाएंगी।

8. मूल विनियमों में, विनियम 25 के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :

25. अधिकारी बैंक द्वारा आवास उपलब्ध कराये जाने के लिए साधिकार हकदार नहीं होगा। किंतु, यदि बैंक चाहे तो वह अधिकारी को आवास उपलब्ध करा सकता है जिसके लिए अधिकारी 1-11-1994 को और उसके बाद से अपने वेतनमान के प्रथम प्रक्रम के 4% के बराबर राशि या आवास के लिए मानक किराये का, जो भी कम हो, भुगतान करेगा। परंतु यदि ऐसे आवास पर फर्नीचर भी उपलब्ध कराया गया हो तो अधिकारी से उसके वेतनमान के प्रथम प्रक्रम के 1% के बराबर अतिरिक्त राशि वसूल की जाएगी।

यदि बैंक द्वारा ऐसी आवास व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है तो बिजली, पानी, गैस और सफाई प्रभार अधिकारी द्वारा दिए जाएंगे।

9. मूल विनियमों में, विनियम 41 के उप-विनियम (4) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात् :

41 (4) 1-6-1995 को और उसके बाद से, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 1 में वर्णित श्रेणी/वेतनमान का अधिकारी स्तंभ 2 में वर्णित तदनुसूची दरों से विराम भत्ता पाने का हकदार होगा :

दैनिक भत्ता (रुपये)

अधिकारियों की श्रेणी/वेतनमान	प्रमुख "ए" वर्ग के नगर	क्षेत्र I	अन्य स्थान
	1	2	
वेतनमान IV और उससे ऊपर के अधिकारी	250.00	200.00	175.00
वेतनमान I/II/III के अधिकारी	200.00	175.00	150.00

परंतु

- (क) यदि अनुपस्थिति की कुल अवधि 8 घंटे से कम किंतु 4 घंटे से अधिक है तो ऊपर बताई गई दरों की आधी दर से विराम भत्ता देय होगा।
 (ख) विभिन्न श्रेणियों/वेतनमानों के अधिकारियों को होटल के वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति की जा सकती है जो नीचे बताई गई सीमा तक भारतीय पर्यटन विकास निगम (आई टी डी सी) के होटलों में एकल आवास कमरे के प्रभारों तक सीमित होगी :

खान-पान खर्च (रुपये)

अधिकारियों की श्रेणी/वेतनमान	ठहरने की पात्रता	प्रमुख "ए" वर्ग के नगर	क्षेत्र I	अन्य स्थान
1	2	3	4	5
वेतनमान VI और VII	4*होटल	250.00	200.00	175.00
वेतनमान IV और V	3*होटल	250.00	200.00	175.00
वेतनमान II और III	2*होटल (अवातानुकूलित)	200.00	175.00	150.00
वेतनमान I	1*होटल (अवातानुकूलित)	200.00	175.00	150.00

(ग) सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार ऊपर परंतु (ख) में निर्धारित सीमाओं से अधिक अतिरिक्त सीमा की प्रतिपूर्ति बोर्ड निर्धारित कर सकता है।

- (घ) यदि आवास की व्यवस्था बैंक की लागत पर बैंक द्वारा की गयी है तो तीन चौथाई विराम भत्ता दिया जाएगा।
 (ङ) यदि भोजन की व्यवस्था बैंक की लागत पर बैंक द्वारा निशुल्क की गई है तो आधा विराम भत्ता दिया जाएगा।
 (च) यदि आवास और भोजन की व्यवस्था बैंक की लागत पर बैंक द्वारा की गई है तो चौथाई विराम भत्ता दिया जाएगा। लेकिन, यदि कोई अधिकारी वास्तविक रूप में हुए खर्च के संबंध में बिल प्रस्तुत किए बिना, घोषणा के आधार पर आवास खर्च का दावा करता है तो उसे चौथाई विराम भत्ता नहीं दिया जाएगा।
 (छ) सभी निरीक्षण अधिकारियों को मुख्यालय से बाहर निरीक्षण ड्यूटी पर विराम के प्रतिदिन के लिए रु. 10/- का अनुपूरक दैनिक भत्ता दिया जा सकता है।

स्पष्टीकरण :

विराम भत्ते की संगणना के लिए "प्रतिदिन" का अभिप्राय है 24 घंटे की अवधि या उसके बाद का कोई भी भाग, जिसकी गणना विमान यात्रा के मामले में प्रस्थान के लिए नियत समय से लेकर पहुंचने के वास्तविक समय तक की जाएगी। यदि अनुपस्थिति की कुल अवधि 24 घंटे से कम है तो "प्रतिदिन" से ऐसी अवधि अभिप्रेत है जो 8 घंटे से कम न हो।

10. मूल विनियमों में, विनियम 42 के उप-विनियम 2 (i) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :

42.2(i) 1-7-1993 को और उसके बाद से, स्थानांतरित अधिकारी को मालगाड़ी से अपने सामान के परिवहन के लिए निम्नलिखित सीमाओं के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाएगी :

वेतन-सीमा	परिवार-सहित	परिवार-रहित
रु. 4,250/-से रु. 6,210/-प्रति माह	3,000 किलोग्राम	1,000 किलोग्राम
रु. 6,211/-प्रति माह और उससे अधिक	पूरा माल डिबा	2,000 किलोग्राम

11. मूल विनियमों में, विनियम 45 के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :

45 भविष्य निधि और पेंशन

- (1) प्रत्येक अधिकारी, यदि वह पहले ही भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो बैंक द्वारा गठित भविष्य निधि का सदस्य बनेगा तथा वह ऐसी निधि को शासित करने वाले नियमों द्वारा आबद्ध होने के लिए सहमत होगा।
- (2) भविष्य निधि नियमों में यह व्यवस्था है कि 1-11-1993 को और उसके बाद से—
 - (क) पेंशन योजना द्वारा शासित अधिकारी के मामले में केवल अधिकारी द्वारा वेतन के 10% की दर से भविष्य निधि में अंशदान, बैंक की ओर से किसी समतुल्य अंशदान के बिना, किया जाएगा।
परन्तु 1-7-1993 से 31-10-1993 के लिए भविष्य निधि में पहले ही किए गए अंशदानों के कारण कोई समायोजन नहीं किया जाएगा।
 - (ख) पेंशन योजना द्वारा शासित न होने वाले अधिकारी के मामले में, अधिकारी, द्वारा भविष्य निधि में अंशदान और बैंक द्वारा समतुल्य अंशदान वेतन 10% की दर से किया जाएगा।
परन्तु 1-7-1993 से 31-10-1993 के लिए भविष्य निधि में पहले ही किए गए अंशदानों के कारण कोई समायोजन नहीं किया जाएगा।
- (3) 29-9-1995 को या उसके बाद बैंक की सेवा में आने वाले अधिकारी पेंशन योजना द्वारा शासित होंगे।
तथापि, निम्नलिखित श्रेणी के अधिकारी पेंशन योजना द्वारा शासित नहीं होंगे :
 - (क) जो अधिकारी 29-9-1995 के पूर्व बैंक की सेवा में था, बशर्ते कि उसने पेंशन योजना के संबंध में बैंक की नोटिस के जवाब में पेंशन योजना का सदस्य होने का विकल्प विशेष रूप से चुन लिया है।
 - (ख) जो अधिकारी 29-9-1995 को या उसके बाद 35 वर्ष या उससे अधिक की आयु में भर्ती हुआ है, और जिसने पेंशन योजना के अनुसार पेंशन का अपना अधिकार छोड़ देना चुना है।

टिप्पणी : भविष्य निधि के प्रयोजन हेतु 'वेतन' का अर्थ है मूल वेतन, जिसमें अवरोध वेतनवृद्धियां, स्थानापन्न भत्ता, व्यावसायिक अर्हता भत्ता और नियत वैयक्तिक भत्ते का वेतनवृद्धि घटक शामिल है।

12. मूल विनियमों में, विनियम 46 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात् :

46. उपदान :

- (1) प्रत्येक अधिकारी, निम्नलिखित स्थितियों में उपदान के लिए पात्र होगा :
 - (क) सेवा-निवृत्ति पर,
 - (ख) मृत्यु पर,
 - (ग) ऐसी निशक्तता पर जिसके कारण बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण-पत्र के अनुसार वह आगे सेवा के लिए अक्षम है,
 - (घ) दस वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद त्याग-पत्र देने पर, या
 - (ङ) दस वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद दण्डस्वरूप सेवा-समाप्ति को छोड़कर अन्य किसी कारण से सेवा-समाप्ति पर।

- (2) अधिकारी को देय उपदान की राशि के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए एक माह का वेतन, जो अधिक से अधिक 15 माह का वेतन हो सकता है।

परन्तु यदि किसी अधिकारी ने 30 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी की है तो वह उपदान के रूप में 30 वर्ष से अधिक की सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए आधे माह के वेतन की दर से अतिरिक्त राशि का पात्र होगा।

परन्तु जिस अधिकारी की सेवाएं 1-7-1993 से 31-10-1994 के दौरान समाप्त हो गई हैं उसके उपदान के प्रयोजन हेतु वेतन से तात्पर्य विनियम 4 के उप-विनियम (1) में उल्लिखित अनुसार वेतनमान से है।

टिप्पणी :

यदि सेवाकाल के पूर्ण वर्षों के अतिरिक्त छह महीने या उससे अधिक की कोई अवधि बचती है तो उस अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर उपदान दिया जाएगा।

सी. एच. राजा राव, महा प्रबन्धक

पाद टिप्पणी :—उपर्युक्त विनियमों में पहले किए गए संशोधन अधिसूचना :

1. सं. 666/3/A-1/292 दिनांक 29 जुलाई, 1991
 2. सं. 666/3/A-1/1424 दिनांक 22 फरवरी, 1993
 3. सं. 666/3/A-1/179 दिनांक 20 मई, 1995
- द्वारा गजट किए गए थे।

ANDHRA BANK

(A Govt. of India Undertaking)

NOTIFICATION

Hyderabad, the 16th January, 1997

Notification No. 666/3/A1/1079.—In exercise of the powers conferred by Section 19 read with sub-section (2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980) the Board of Directors of Andhra Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations, namely :—

1. Short title and commencement:

- (1) These Regulations may be called Andhra Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 1996.
- (2) Save as otherwise expressly provided in these Regulations, these Regulations shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
2. In the Andhra Bank (Officers') Service Regulations, 1982 (hereinafter referred to as principal Regulations), for Regulation 4, the following may be substituted, namely :
 - 4 (1) On and from 1-11-1987, the scales of pay specified against each grade shall be as under :—
 - (a) Top Executive Grade :
 - Scale VII Rs. 6400-150-7000
 - Scale VI Rs. 5950-150-6550
 - (b) Senior Management Grade :
 - Scale V Rs. 5350-150-5950
 - Scale IV Rs. 4520-130-4910-140-5050-150-5350
 - (c) Middle Management Grade :
 - Scale III Rs. 4020-120-4260-130-4910
 - Scale II Rs. 3060-120-4260-130-4390
 - (d) Junior Management Grade :
 - Scale I Rs. 2100-120-4020

598-21(95)-3

4(2) On and from 1-7-1993, the scales of pay specified against each grade shall be revised as under :

(a) Top Executive Grade:

Scale VII Rs. 12650-300-13250-350-13600-400-14000

Scale VI Rs. 11450-300-12650

(b) Senior Management Grade :

Scale V Rs. 10450-250-11450

Scale IV Rs. 8970-230-9200-250-10450

(c) Middle Management Grade :

Scale III Rs. 8050-230-9200-250-9700

Scale II Rs. 6210-230-8740

(d) Junior Management Grade :

Scale I Rs. 4250-230-4940-350-5290-230-8050

4(3) Nothing in sub-regulations (1) and (2) shall be construed as requiring the Bank to have at all time, Officers serving in all these grades.

3. In principal Regulations, for Regulation 5, the following may be substituted, namely :—

5(1) Subject to the provisions of Regulation 4 (2), on and from 1-11-1992, the increments shall be granted subject to the following sub-clauses :—

(a) The increments specified in the scales of pay set out in Regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the months in which these fall due.

(b) Officers in Scale I and Scale II, 1 year after reaching the maximum in their respective scales, shall be granted further increments including stagnation increment(s) in the next higher scale only as specified in (c) below subject to their crossing the efficiency bar as per guidelines of the Government.

(c) Officers including those referred to in (b) above who reach the maximum of the Middle Management Grade Scales II and III shall draw stagnation increment(s) for every three completed years of service after reaching the last stage of the Scale II or Scale III as the case may be subject to a maximum of the two such increments of Rs. 230/- each for officers in the last stage of Scale II and one such increment of Rs. 250/- for officers in the last stage of Scale III.

Provided that on and from 1-11-1994 officers in substantive Scale III i.e., those who are recruited in or promoted to Scale III shall be eligible for second stagnation increment three years after having received the first stagnation increment.

Note : Grant of such increments in the next higher scale shall not amount to promotion. Officers even after receipt of such increments shall continue to get privileges, perquisites, duties, responsibilities or posts of their substantive Scale I or Scale II as the case may be.

(2) An additional increment shall be granted in the scale of pay for passing each part of Certified Associate of Indian Institute of Bankers Examination on or after the appointed date.

EXPLANATION I :

In the case of an officer who has passed Part I or Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers Examination as an officer before the appointed date, the additional increment, or increment as the case may be, shall be given effect to from the appointed date provided that he has not received any increment or received only one increment, for passing both parts of the said Examination.

EXPLANATION II :

(a) On and from 1-11-1987 officers who reach or have reached the maximum in the pay scale and are unable to move further except by way of promotion shall subject to Government guidelines, if any, be granted Professional Qualification Allowance in lieu of additional increments in consideration of passing CAIIB Examination as under :—

Those who have passed only part I of CAIIB

(i) Rs. 100/- p.m. after one year

Rs. 75/- shall rank for superannuation benefits.

Those who have passed both parts of CAIIB

(i) Rs. 100/- p.m. after one year, of which Rs. 75/- shall rank for superannuation benefits.

(ii) Rs. 250/- p.m. after two years, of which Rs. 200/- shall rank for superannuation benefits.

(b) On and from 1-11-1994, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Allowance shall stand revised as under :—

Those who have passed only Part I of CAIIB	(i)	Rs.120 p.m. after one year on reaching top of the scale.
Those who have passed both parts of CAIIB	(i)	Rs.120 p.m. after one year on reaching top of the scale.
	(ii)	Rs.300 p.m. after two years on reaching top of the scale.

Provided that officers who are eligible to draw Fixed Personal Allowance in terms of Regulation 5(3)(b) shall draw Professional Qualification Allowance one year/two years after receipt of such Fixed Personal Allowance respectively for Parts I and II as the case may be.

Note: (i) If an officer who is in receipt of professional Qualification Allowance is promoted to next higher scale, he shall be granted, on fitment into such higher scale, additional increment(s) for passing CAIIB to the extent increments are available in the scale and if no increments are available in the scale or only one increment is available in the scale, the officer shall be eligible for Professional Qualification Allowance in lieu of increment(s).

(ii) On and from 1-11-1994 revised Professional Qualification Allowance shall rank for Dearness Allowance, House Rent Allowance and Superannuation benefits.

3(a) All Officers who are in the bank's permanent service as on 1st November, 1993 will get one advance increment in the scale of pay. Officers who are on probation on 1st November, 1993 will get one advance increment one year after confirmation.

Note : There shall be no change in the date of annual increment because of advance increment.

(b) An officer who is at the maximum of the scale or who is in receipt of stagnation increment(s) as on 1st November, 1993, will draw a Fixed Personal Allowance from 1st November, 1993 which shall be equivalent to an amount of last increment drawn plus dearness allowance payable thereon as on 1st November, 1993, plus house rent allowance, at such rates as applicable in terms of Regulation 22. The Fixed Personal Allowance given hereunder together with House Rent Allowance, if any, shall remain frozen for the entire period of service :

Increment Component	DA as on 1-11-1993	Total F.P.A. Payable where bank's accommodation is provided.
(A)	(B)	(C)
Rs.	Rs.	Rs.
230	5.79	236
250	6.30	257
300	7.56	308
400	10.08	411

Note: (i) F.P.A. as indicated in (C) above shall be payable to those officer employees who are provided with bank's accommodation.

(ii) F.P.A. for officers eligible for House Rent Allowance shall be (A) + (B) + House Rent Allowance drawn by the concerned officer employees when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub-regulation (2) of Regulation 4 is earned.

(iii) Professional Qualification Allowance, if any, payable in the year of receipt of F.P.A. shall stand shifted to next year.

(iv) The increment component of Fixed Personal Allowance shall rank for superannuation benefits.

(c) An officer who has earned this advance increment shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance as mentioned in (b) above, one year after reaching the maximum of the scale.

4. In principal Regulations, for Regulation 21, the following may be substituted, namely :—

21(1) On and from 1-11-1987, Dearness Allowance Scheme shall be as under :—

(i) Dearness Allowance shall be payable for every rise or fall of 4 points over 600 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100.

(ii) Dearness Allowance shall be payable as per the following rates :—

- (i) 0.67% of 'pay' up to Rs. 2500 plus,
- (ii) 0.55% of 'pay' above Rs. 2500 to Rs. 4000 plus,
- (iii) 0.33% of 'pay' above Rs. 4000 to Rs. 4260 plus,
- (iv) 0.17% of 'pay' above Rs. 4260.

21(2) On and from 1-7-1993, Dearness Allowance Scheme shall be as under :—

(i) Dearness Allowance shall be payable for every rise or fall of 4 points over 1148 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100.

(ii) Dearness Allowance shall be payable as per the following rates :—

- (a) 0.35% of 'pay' up to Rs. 4800 plus,
- (b) 0.29% of 'pay' above Rs. 4800 to Rs. 7700 plus,
- (c) 0.17% of 'pay' above Rs. 7700 to Rs. 8200 plus,
- (d) 0.09% of 'pay' above Rs. 8200.

Note: (i) 'pay' for the purpose of Dearness Allowance shall mean basic pay including stagnation increments.

(ii) Professional Qualification Allowance shall rank for dearness allowance with effect from 1-11-1994.

5. In principal Regulations, for sub-regulations (1) and (2) of Regulation 22, the following may be substituted, namely,

22(1) Where an officer, is provided with residential accommodation by the bank, on and from 1-11-1994, a sum equal to 4% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, will be recovered from him.

22(2) Where an officer, is not provided any residential accommodation by the bank, he shall be eligible on and from 1-11-1992 for House Rent Allowance at the following rates :—

Column I	Column II
Where the place of work is in	HRA payable shall be
(i) Major 'A' Class cities specified as such from time to time in accordance with the guidelines of the Government & Project Area Centres in Group 'A'	13% of the pay p.m.
(ii) Other places in Area I and Project Area Centres in Group 'B'	12% of the pay p.m.
(iii) Area II and State Capitals and Capitals of Union Territories not covered by (i) and (ii) above.	10-½ % of the pay p.m.
(iv) Area III	9-½ % of the pay p.m..

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for his residential accommodation in excess over 4% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or 150% of the House Rent Allowance payable as per Column II above whichever is lower.

Note: (i) 'Pay' for the purpose of House Rent Allowance shall mean basic pay including stagnation increments in terms of revised pay scales as on 1-7-1993.

(ii) Professional Qualification Allowance shall rank for House Rent Allowance with effect from 1-11-1994.

6. In principal Regulations, for sub-regulation (i) of Regulation 23, the following may be substituted, namely :—

23 (i) On and from 1-11-1993, if he is serving in a place mentioned in column 1 of the Table below, a City Compensatory Allowance at the rate mentioned in column 2 thereof against that place shall be payable.

Places		Rates
1		2
(a)	Places in Area I and in the State of Goa	4½% of basic pay subject to a maximum of Rs. 335 per month.
(b)	Places with population of 5 lakhs and over and State Capitals and Chandigarh, Pondicherry and Port Blair not covered by (a) above.	3½% of basic pay subject to a maximum of Rs. 230 per month.

7. In principal Regulations, for Regulation 24, the following may be substituted, namely :—

24 (1) An officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses actually incurred by him in respect of himself and his family on the following basis, namely :—

(a) Medical Expenses

On and from 1-11-1994 reimbursement of medical expenses to an officer in the grade specified in column 1 of the Table below and his family may be made on the strength of the officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed subject to the limit specified in column 2 thereof :—

TABLE

Grade	Reimbursement limit p.a.
1	2
Junior Management and Middle Management Grade	Rs. 1,500
Senior Management and Top Executive Grade	Rs. 2,000

Note : (i) An officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above.

(ii) For the year 1994 the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for two months, i.e., November and December, 1994.

Explanation :

'Family' of an officer for the purpose of this regulation shall consist of spouse, wholly dependent children and wholly dependent parents only.

(b) Hospitalisation Expenses :

- (i) On and from 1-1-1994, hospitalisation charges will be reimbursed to the extent of 100% in the case of an officer and 75% in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalisation. Reimbursement on the basis of bills, vouchers, etc., of expenses incurred shall be subject to ceilings determined from time to time in accordance with the guidelines of the Government.
- (ii) The officers or members of their families (as the case may be) are expected to secure admission in a Government or Municipal Hospital or any private hospital, i.e., hospitals under the management of a Trust, Charitable Institution or a religious mission. But in unavoidable circumstances the officers or their family members or both may avail themselves of the services of one of the approved private nursing homes or private hospitals approved by the Bank. Reimbursement in such cases should, however, be restricted to the amount which would have been reimbursable in case the patient was admitted to one of the hospitals mentioned above.
- (iii) On and from 1-11-1994, medical expenses incurred in respect of the following diseases which need domiciliary treatment as may be certified by the recognised hospital authorities and Bank's medical officer shall be deemed as hospitalisation expenses and reimbursed to the extent of 100% in case of an officer and 75% in the case of his family members:—

Cancer, Leukaemia, Thalassemia, Tuberculosis, Paralysis, Cardiac Ailment, Leprosy, Kidney Ailment, Epilepsy, Parkinson's Disease, Psychiatric Disorder and Diabetes.

598-2.1/97-4

- Note :** (1) The cost of medicines etc. in respect of domiciliary treatment shall be reimbursed for the period stated in the Specialist's prescription. If no period is stated, the prescription for the purposes of reimbursement shall be valid for a period not exceeding 90 days.
- (2) Notwithstanding the medical benefits (including hospitalisation etc.) listed in sub-Regulation (1) above and in complete substitution of the same, the Board may decide to retain in an unaltered form medical benefits (including hospitalisation, etc.) as available in the Bank on the appointed date and if the Board so decides, all officers shall be eligible for reimbursement of medical expenses only as per the terms and conditions obtaining in the Bank on the appointed date for grant of medical benefits (including hospitalisation, etc.).
- (3) Medical Aid and Hospitalisation facilities shall also be admissible to the officers who are placed under suspension.
- (8) In Principal Regulations, for Regulation 25, the following may be substituted, namely :—

25. No officer shall be entitled as of right to be provided with residential accommodation by the Bank. It shall, however, be open to the bank to provide residential accommodation on payment by the officer on and from 1-11-1994 a sum equal to 4% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation whichever is less :

Provided that a further sum equal to 1% of basic pay in the first stage of the scale of pay will be recovered by the Bank from an officer if furniture is provided at such residence :

Provided further that, where such residential accommodation is provided by the bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.

- (9) In principal Regulations, for sub-regulation (4) of Regulation 41, the following may be substituted, namely :—

41(4) On and from 1-6-1995 an officer in the Grades/Scales set out in column 1 of the table below shall be entitled to Halting Allowance at the corresponding rates set out in column 2 thereof :

TABLE

Grades/Scales of officers	Daily Allowance (Rupees)		
	Major 'A' Classes Cities	Area I	Other places
1	2		
Officers in Scale IV and above	250.00	200.00	175.00
Officers in Scale I/II/III	200.00	175.00	150.00

Provided that

- (a) Where the total period of absence is less than 8 hours but more than 4 hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.
- (b) Officers in various Grades/Scales may be reimbursed the actual hotel expenses, restricting to single room accommodation charge in ITDC Hotels, subject to the limits as given below :—

Boarding Charges (Rupees)

Grades/Scales of officers	Eligibility to stay	Major 'A' class cities	Area I	Other places
1	2	3	4	5
Scale VI & VII	4* Hotel	250.00	200.00	175.00
Scale IV & V	3* Hotel	250.00	200.00	175.00
Scale II & III	2* Hotel	200.00	175.00	150.00
	(Non-AC)			
Scale I	1* Hotel	200.00	175.00	150.00
	(Non-AC)			

- (c) The Board may prescribe reimbursement of additional limit in excess of the limits prescribed in proviso (b) above in accordance with the guidelines of the Government.
- (d) Where lodging is provided at bank's cost/arranged through the bank free of cost, 3/4th of the Halting Allowance will be admissible.
- (e) Where boarding is provided at bank's cost/arranged through the bank free of cost, 1/2 of the Halting Allowance will be admissible.
- (f) Where lodging and boarding are provided at bank's cost/arranged through the bank free of cost, 1/4th of the Halting Allowance will be admissible. Where, however, an officer claims boarding expenses on a declaration basis without production of bills for actual expenses incurred, then he shall not be eligible for 1/4th of the Halting Allowance.
- (g) A supplementary diem allowance of Rs. 10/- per day of halt outside headquarters on inspection duty may be paid to all inspecting officers.

Explantation :

For the purpose of computing Halting Allowance 'per diem' shall mean each period of 24 hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival. Where the total period of absence is less than 24 hours, 'per diem' shall mean a period of not less than 8 hours.

10. In principal Regulations, for sub-regulation 2(1) of Regulation 42, the following may be substituted, namely :—

42 (2) (i) On and from 1-7-1993 an officer on transfer will be reimbursed his expenses for transporting his baggage by goods train upto the following limits :—

Pay Range	Where he has family	Where he has no family
Rs. 4250/- p.m. to Rs. 6210/- p.m.	3000 kgs.	1000 kgs.
Rs. 6211/- p.m. and above.	Full Wagon	2000 kgs.

11. In principal Regulations, for Regulation 45, the following may be substituted, namely :—

45. Provident Fund and Pension

- (1) Every officer shall become a member of the Provident Fund constituted by the Bank, unless he is already a member of that Fund and shall agree to be bound by the rules governing such fund.
- (2) The Provident Fund rules framed shall provide that on and from 1-11-1993 —

- (a) in case of an officer governed by the Pension Scheme, contribution to the Provident Fund shall be made only by the officer at the rate of 10% of pay without any matching contribution on the part of the bank.

Provided that no adjustment on account of provident fund contributions already made for the period 1-7-1993 to 31-10-1993 shall be made.

- (b) In case of an officer not governed by the Pension Scheme, contribution to Provident Fund by the officer and a matching contribution by the bank shall be made at the rate of 10% of pay.

Provided that no adjustment on account of provident fund contributions already made for the period 1-7-1993 to 31-10-1993 shall be made.

- (3) Officers joining the bank's service on or after 29-9-1995 shall be governed by the Pension Scheme.

Provided that the following categories of officers shall not be covered by the Pension Scheme :

- (a) an officer who was in service of the bank prior to 29-9-1995, unless he has specifically exercised an option to become member of the Pension Scheme in response to bank's notice to that effect.
- (b) an officer who is recruited on or after 29-9-1995 at the age of 35 years and above, and who has elected to forego his right to pension in terms of the pension scheme.

Note : 'Pay' for the purpose of Provident Fund shall mean basic pay including Stagnation Increments, Officiating Allowance, Professional Qualification Allowance and increment component of Fixed Personal Allowance.

12. In principal Regulations, for Regulation 46, the following may be substituted, namely :—

46. Gratuity :

(1) Every officer, shall be eligible for gratuity on :—

- (a) retirement
- (b) death
- (c) disablement rendering him unfit for further service as certified by a medical officer approved by the Bank;
- (d) resignation after completing ten years of continuous service; or
- (e) termination of service in any other way except by way of punishment after completion of 10 years of service.

(2) The amount of gratuity payable to an officer shall be one month's pay for every completed year of service, subject to a maximum of 15 months' pay.

Provided that where an officer has completed more than 30 years of service, he shall be eligible by way of gratuity for an additional amount at the rate of one half of a month's pay for each completed year of service beyond 30 years.

Provided further that pay for the purpose of Gratuity for an officer who ceased to be in service during the period 1-7-1993 to 31-10-1994 shall be with regard to scale of pay as specified in sub-regulation (1) of regulation 4.

Note :

If the fraction of service beyond completed years of service is 6 months or more, gratuity will be paid pro-rata for the period.

CH. RAJA RAO, General Manager

Foot Note : The amendments carried out earlier in the above Regulations were Gazetted *vide* Notification Nos.

- (1) 666/3/A-1/292 dated 29th July, 1991.
- (2) 666/3/A-1/1424 dated 22nd February, 1993.
- (3) 666/3/A-1/179 dated 20th May, 1995.